फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 304 प्रभात जयपुर, रविवार 7 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

RABINDRANATH TAGORE ON CELLULOID

Strir Patra (The letter from the Wife) has to be one of the earliest depictions in Bangla literature with a bold statement on the emancipation of a woman

The Story of Irani Cafés in India

He Turned Soap into Swadeshi Strength

भारत ने विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए ''रैड कारपेट'' बिछाया

भारत का यह निर्णय, स्थिर, दीर्घकालीन इन्वैस्टर, जैसे पैंशन फण्ड, इंश्योरैंस कंपनियों आदि का पैसा अपने बॉण्ड मार्केट में निवेश करवाने के लिए है

- अब विदेशी निवेशक को सरकारी सिक्यूरिटीज़ में लगाए गए पैसे से अर्जित ब्याज आदि आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और अब सरकारी सिक्यूरिटीज़ में पैसा लगाने की शर्तें भी खत्म कर दी गई हैं।
- सरकार को आशा है, इस निर्णय से रूपया मजबूत होगा व सरकार की धन उधार लेने की क्षमता भी सुदृढ़ होगी। अब तक विदेशी निवेशक को गवरमैंट सिक्यूरिटीज़ में ''लॉंग टर्म'' पैसा लगाने पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था तथा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमैंट पर, जो एक साल के अंदर बेच दिया जाता था, पर बीस प्रतिशत टैक्स देना होता था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के खाते में।
- सरकार इन सभी रियायतों के माध्यम से संदेश दे दे रही है विदेशी निवेशक को कि नए उभरते मार्केट (एमर्जिंग मार्क़ेट्स) में पूँजी लगाने की दृष्टि से भारत एक आकर्षक विकल्प है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जून। विदेशी निवेशकों को अब तक की सबसे उदार कर रियायतों में से एक देते हुए सरकार ने इण्डियन गवरमैंट सिक्यूरिटीज़ (भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों) में विदेशी निवेश पर टैक्स का बोझ लगभग समाप्त कर दिया है। आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के माध्यम से विदेशी निवेशकों को अब सरकारी बॉन्ड में निवेश से होने वाली इन्टरैस्ट इन्कम और कैपिटल गेन्स, दोनों पर टैक्स से छूट दे दी गई है, साथ ही निवेश से जुड़े कई प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है। यह कदम वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है और दिखाता है कि बाहरी फायनैंसिंग की बढ़ती जरूरतों के समय सरकार देश के ऋण बाजार में लंबे समय के लिए विदेशी निवेश लाने के लिए कितनी गंभीर है।

1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इस अध्यादेश के तहत आयकर अधिनियम, 2025 की छटी अनुसूची में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार फॉरैन इंस्टीट्यूटनल इन्वैस्टर्स (एफआईआई) को सरकारी सिक्यूरिटीज़ से मिलने वाले ब्याज और ऐसी सिक्यूरिटीज़ को बेचने, बदलने या ट्रांसफर करने से होने वाले लाभ पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, हालांकि यह छूट निर्धारित डिस्क्लोज़र ज़रुरतों के अधीन होगी। इसी प्रकार की सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बैंक फॉर इन्टरनैशनल सैटलमैंट्स -बी.आई.एस.) को भी दी गई हैं, जिसे अक्सर केन्द्रीय बैंकों का केन्द्रीय बैंक कहा जाता है।

ये टैक्स रियायतें काफी महत्वपूर्ण हैं। अब तक विदेशी निवेशकों को

(शेष पृष्ठ 4 पर)

ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता

- नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं।

नई दिल्ली, 06 जून। भारतीय शतरंज के वंडर बॉय आर प्रज्ञानंद ने विश्व पटल पर एक और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। चेन्नई के 20 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे के स्टावेंजर में खेले गए टूर्नामेंट के 10वें और अंतिम दौर में जर्मनी के विन्सेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ उन्होंने कुल 18 अंक हासिल किए और अमेरिका के ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो (17 अंक) को पीछे छोड़ते हुए चैंपियन बने। प्रज्ञानानंद की यह सफलता टूर्नामेंट इतिहास की सबसे शानदार वापसी में से एक मानी जा रही है। छह राउंड के बाद वे छह खिलाड़ियों में अंतिम स्थान पर थे, लेकिन इसके बाद लगातार चार जीत दर्ज कर उन्होंने शानदार वापसी की और खिताबी दौड़ में खुद को आगे कर लिया।

उनकी लगातार जीत के क्रम में विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन के

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बैंगलोर के सोने के व्यापारी राजेश एक्सपोर्ट का 15.51 लाख करोड़ का स्कैम उजागर हुआ

सेबी द्वारा की गई जाँच ने तीस साल पुराने हर्षद मेहता स्कैम की याद ताजा की

- राजेश एक्सपोर्ट कई वर्षों से अपनी आय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी बैलैंस शीट में दर्ज कर रहा था। अन्ततोगत्वा उसकी कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो गई।
- राजेश एक्सपोर्ट की ''नेट वर्थ'' इस प्रकार बहुत ''सुदृढ़'' हो गई तथा जनता में उसकी कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे तथा छोटे-छोटे निवेशकों के अलावा स्थापित कंपनियाँ, जैसे एलआईसी भी इसके शिंकजे में फंस गईं और कंपनी के शेयर्स में काफी पैसा लगा दिया और शीघ्र ही 10 प्रतिशत की सीमा भी पार कर गई।
- पुराना बैंक, कैनरा बैंक भी झांसे में आ गया और राजेश एक्सपोर्ट की स्कीम्स को फंड करने लगा।
- राजेश एक्सपोर्ट ने बाज़ार में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए स्विट्ज़रलैण्ड की एक पुरानी कंपनी भी खरीदी।
- अब, अन्ततोगत्वा सारे कारनामे उजागर होने के बाद, कंपनी के शेयर धूल चाट रहे हैं तथा लाखों छोटे-बड़े निवेशक अपनी गाँठ की कमाई गंवाकर रोते फिर रहे हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जून। सिक्यूरिटीज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) की हालिया जांच में बेंगलुरु स्थित सोने के कारोबारी और स्वर्ण आभूषण विक्रेता राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा किये गये लगभग 15.51 लाख करोड़ रुपये के विशाल कॉरपोरेट घोटाले का खुलासा हुआ है।

यह कहानी लगभग तीस वर्ष पहले हुए हर्षद मेहता घोटाले जैसे अन्य वित्तीय घोटालों से मिलती-जुलती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में खातों में काल्पनिक मूल्य दिखाकर उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कोई मूल्य मौजूद नहीं होता।

राजेश एक्सपोर्ट्स ने वर्षों तक अपनी आय और राजस्व के आंकड़ों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, जिससे उसकी बैलेंस शीट भी वास्तविकता से कहीं अधिक मजबूत दिखाई गई। कंपनी भारत के स्टॉक मार्केट में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत थी और भारत के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थी। इसलिए वह सेबी के लिस्टिंग नियमों और अकाउंटिंग-पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों के दायरे में आती थी।

इन नियमों को दरकिनार करते हुए, रैवेन्यू की बढ़ा- चढ़ाकर बताई गई कहानी को इन्वैस्टर्स ने कंपनी की नैट वर्थ मान लिया। इससे आम जनता ने

(शेष पृष्ठ 4 पर)

लंदन में सवालों से घिरे सीजेआई सूर्यकांत

सीजेआई सूर्यकांत ''ऑर्टिफिशल इन्टैलिजैंस और इन्टरनैशनल लॉ'' पर लैक्चर देने के लिए युनिवर्सिटी ऑफ लंदन बर्कबैक गए थे

- लैक्चर के बाद शुरु हुए सवाल जवाब में कुछ लोगों ने सीजेआई से भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता और सीजेआई की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सवाल पूछे, जिससे सीजेआई की स्थिति काफी अटपटी हो गई।
- बाद में मॉडरेटर ने हालात को संभाला और कहा, चर्चा के विषय से संबंधित सवाल ही लिए जाएंगे।
- इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जून। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के लंदन विश्वविद्यालय, बर्कबेक में दिए गए व्याख्यान के दौरान विवाद खड़ा हो गया, जब उपस्थित लोगों ने भारत में असहमति और उनकी हालिया ''कॉकरोच'' टिप्पणियों को लेकर उनसे सवाल किए, जिससे प्रश्नोत्तर सत्र अवरुद्ध हो गया।

यह घटना 4 जून को हुई, जब सीजेआई ने ''कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरराष्ट्रीय कानून'' पर व्याख्यान दिया।

इंटरैक्टिव सत्र के दौरान, एक उपस्थित व्यक्ति ने सीजेआई सूर्यकांत से भारत के लोकतांत्रिक रिकॉर्ड और असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता के बारे में सवाल किया।

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स में, उपस्थित व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है:

''हम अब देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कानूनी पर्यवेक्षकों से सुन रहे हैं कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता को लेकर गहरी चिंता है। और ऐसा लगता है कि यह शत्रुता उनके भाषण में भी कहीं न कहीं परिलक्षित होती है और यह बहुत प्रचारित भी है।''

एक अन्य उपस्थित व्यक्ति ने से 15 मई को अदालत में उनके द्वारा किए गए और बाद में भारत में व्यापक बहस

(शेष पृष्ठ 4 पर)

34 साल पहले हटाये कर्मचारी का बकाया नहीं दिया तो क्लार्क्स आमेर सील होगा

- श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में होटल क्लार्क्स आमेर को बकाया राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान 8 जून तक करने को कहा।

जयपुर, 6 जून। श्रम न्यायालय ने 34 साल पहले गलत तरीके से हटाए गए कर्मचारी को अदालती आदेश के बावजूद बकाया भुगतान नहीं करने पर होटल क्लार्क्स आमेर प्रबंधन को कहा है कि वह प्रार्थी कर्मचारी को मांगी गई राशि की एक चौथाई राशि के तौर पर छह लाख रुपए और 25 हजार रुपए का हर्जाना 8 जून तक अदा करे। और यदि राशि जमा नहीं हुई तो उसी दिन कुर्की वारंट जारी कर पुलिस कमिश्नर को भेजे जाए। इसके साथ ही होटल को सील किए जाने के दौरान होटल प्रबंधन के

(शेष पृष्ठ 4 पर)

चुनाव प्रचार के मुद्दों पर सीपीएम ने कांग्रेस से सफाई मांगी

सीपीएम महासचिव बेबी जॉन ने चिट्ठी लिख कर पूछा, कांग्रेस इस आरोप का जवाब दे कि सीपीएम और भाजपा में सांठ-गांठ है

- सीपीएम ने इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दलों को यह चिट्ठी भेजी है। सोमवार 8 जून को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले सीपीएम ने यह कदम उठाकर बैठक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
- सीपीएम ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, राहुल, प्रियंका व मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषणों में बार-बार यह कहा और यह भी कहा कि प्र.मंत्री मोदी और सीपीएम के मु.मंत्री पिनराई विजयन के बीच ''अंडरस्टैंडिग'' है।
- सीपीएम ने अपने पत्र में लिखा कि यह मात्र चुनावी प्रतिद्वंदिता नहीं थी, ऐसे आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक इंडिया ब्लॉक बनाने के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह रहेगा।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जून। सोमवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले, कांग्रेस और सीपीएम (मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी) के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

हालिया विधानसभा चुनावों के बाद आयोजित महत्वपूर्ण बैठक से कुछ दिन पहले, सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान उठाए गए विवादित मुद्दे को दोबारा उठाया है। कांग्रेस ने हाल ही में चुनावों में सीपीएम पर भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था।

बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में केरल में सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस के चुनाव प्रसार की आलोचना की है। बताया जाता है कि पत्र की प्रतियां इंडिया ब्लॉक के अन्य सदस्यों को भी भेजी गई हैं।

बेबी ने पत्र में कहा है कि ''राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा बार-बार लगाए गए आरोप चुनावी प्रतिस्पर्धा से परे जाकर, भाजपा के खिलाफ उस गठबंधन की मजबूती को कमज़ोर कर रहे हैं, जो भाजपा को संयुक्त चुनौती देने के लिए बनाया गया था।'' उन्होंने कांग्रेस की उस प्रचार रणनीति की भी आलोचना की जिसमें कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच कोई ''विशेष समझबूझ'' है।

सीपीएम महासचिव बेबी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के गठन के बाद से पार्टी हमेशा विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में काम करती रही है। उन्होने कांग्रेस पर दोहरे मानक अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सीपीएम के साथ साझेदारी

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की

- बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार किया गया।

नई दिल्ली, 06 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देने के उपायों पर व्यापक चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विचारों और नीतिगत उपायों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि उन्होंने आर्थिक सलाहकार परिषद की

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी की ज़ैड प्लस सुरक्षा हटाई गई

नाराज़ लालू यादव ने नई सुरक्षा टीम को वापस लौटा दिया और अब आरजेडी कार्यकर्ता लाठी-डंडे लेकर आवास की सुरक्षा कर रहे हैं

- बिहार सरकार ने वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा स्थिति को अपडेट किया है, इसके बाद लालू यादव व राबड़ी देवी को दी गई ज़ैड प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई। नई टीम में बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स के जवान, पटना डिस्ट्रिक्ट फोर्स के दो गार्ड, एक पायलट कार व एक बुलेट प्रूफ कार शामिल है।
- लालू के पुत्र तथा बिहार में नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव ने भी अपनी वाय श्रेणी की सुरक्षा लौटा दी है।
- राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, को उनका सरकारी आवास, 10, सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया है। जो इसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्यादा ही उत्साहित हैं, उनकी सरकार भले ही मुझे जबर्दस्ती घर से निकाल दे, मैं घर खाली नहीं करूँगी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जून। बिहार सरकार द्वारा उनकी ज़ैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस लिए जाने से नाराज़ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने शनिवार सुबह नई सुरक्षा टीम को वापस भेज दिया।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के इन वरिष्ठ नेताओं को इस सप्ताह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस-बीएसएपी) की सुरक्षा प्रदान की गई थी, क्योंकि राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद उनकी सर्वोच्च श्रेणी की ज़ैड प्लस सुरक्षा हटा ली थी।

लेकिन उन्होंने पटना स्थित अपने 10, सर्कुलर रोड आवास के बाहर तैनात नये सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया।

कुछ आरजेडी कार्यकर्ता भी उनके घर की सुरक्षा के लिये लाठियाँ लेकर खड़े दिखाई दिए।

वरिष्ठ नेताओं के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था में बीएसएपी के दो से आठ गृह रक्षक, पटना डिस्ट्रिक्ट फोर्स के दो अंगरक्षक तथा एक पायलट वाहन और बुलेटप्रूफ कार शामिल हैं।

उनके पुत्र और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपना वाई- श्रेणी का सुरक्षा कवर वापस भेज दिया।

लालू यादव और राबड़ी देवी की पुत्री रोहिणी आचार्य ने कहा कि सुरक्षा हटाने का निर्णय '' उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से'' लिया गया है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, ''सुरक्षा में इतनी बड़ी कटौती के बाद केवल दिखावे की सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए राबड़ी देवी जी ने अपने सरकारी आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस भेजने का निर्णय लिया है।''

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने आरजेडी समर्थकों से अपील की कि वे 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर एकत्र होकर यह ''सीधा, स्पष्ट और कड़ा संदेश'' दें कि वे ही यादव परिवार के ''सच्चे रक्षक और सुरक्षा कवच'' हैं।

आचार्य ने कहा, ''पूरा देश और बिहार देख रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार

(शेष पृष्ठ 4 पर)

अन्नाद्रमुक में अब तक की सबसे बड़ी बगावत

- पार्टी के चार पूर्व मंत्रियों सहित 300 से ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय की पार्टी में शामिल हो गए।

नई दिल्ली, 06 जून। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार और आंतरिक कलह से जूझ रही मुख्य विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक को शनिवार को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा, जब उसके चार पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं समेत, 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सत्ताधारी दल तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) का दामन थाम लिया।

चेन्नई के पनायुर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में इन सभी नेताओं को टीवीके की सदस्यता दिलाई गई। मुख्यमंत्री सी.

(शेष पृष्ठ 4 पर)